राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम

विधि (कक्षीय प्रस्ताव) विधा
(भाग-2)
अधिसूचना

जयपुर, दिन 18, 2017

संख्या प. 2 (24) विधि-2/2017-राजस्थान राज्य विधान-मंडल का विधिमंडल अधिनियम, जिसे राज्यपाल भारत की अनुमति दिनांक 17 मई, 2016 को प्राप्त हुई, उत्तराखंड विधानसभा की सुचना के प्रारम्भ विधिमंडल द्वारा जारी किया गया है।

राजस्थान सरकारीकार्य (राज्यसभा संसदीय) अधिनियम, 2017
(2017 का अधिनियम संख्या 27)
[राज्यपाल की अनुमति दिनांक 17 मई, 2017 को प्राप्त हुई]

राजस्थान सरकारीकार्य अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत सरकार के अधीन वर्तमान में राजस्थान राज्य विधान-मंडल निम्नलिखित अधिनियम बनाए हैं-

1. कक्षीय नाम और प्रारूप: (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सरकारीकृति (कक्षीय संसदीय) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह पुराना प्रकाशित है।

2. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 45 का संशोधन:- राजस्थान सरकारीकृति अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें आगे नूतन अधिनियम बनाया गया है, की धारा 45 की उप-धारा (1) के विषय में बन्द (d) और (f) के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्तावित किया जायेगा, अयोध्या:-
3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की शराात 55 का संशोधन— मुल अधिनियम की पारा 55 की उप-शराात (3), में—

(i) विधानसभा वर्ग (ii) के प्रति और विधानसभा वर्ग (iii) से पूर्व में विनियमित नया वर्ग अलग-स्थापित किया जाेंगा, अथवा—

(ii) केवल एक या अधिक, सर्वजनिक मार्ग, मेहनती और साधनों से संबंधित प्रदेश व परिवारों के लिए एक समिति, इस्तेमाल किया जाएगा, और दो समितियों के लिए दो समितियाँ की जाेंगी। और

(ii) विधानसभा वर्ग (iv) के प्रति और विधानसभा वर्ग (v) से पूर्व में विनियमित नया वर्ग अलग-स्थापित किया जाेंगा, अथवा—

(iv-k) मार्गों और अन्य विधानों, संबंधित व्यवस्था के लिए संबंधित प्रवासी बीमा के लिए संबंधित विधान उपवर्ग की जाेंगी।

4. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 21 की शराात 55 के संशोधन— मुल अधिनियम की विधान पारा 21 के त्यों पर विनियमित प्रतिस्थापित किया जाेंगा, अथवा—
LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, May 18, 2017
No. F. 2 (24) Vidihi/2/2017.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 27 of 2017).

(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (FOURTH AMENDMENT) ACT, 2017
(Act No. 27 of 2017)
[Received the assent of the Governor on the 17th day of May, 2017]

An Act

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:

3
1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Fourth Amendment) Act, 2017.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 45, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing clauses (r) and (s) of sub-section (1) of section 45 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(r) promoting population control, family welfare, small family norma, welfare of women and children development,

(s) preparing plans for economic development, social justice, poverty alleviation, slum improvement, public distribution system and providing food to the needy persons;"

3. Amendment of section 55, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (3) of section 55 of the principal Act,-

(i) after the existing clause (i) and before the existing clause (ii), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(i-a) one or more lighting public streets, places and buildings committees:

Provided that every Municipality may constitute one committee for wards upto fifty, two committees for fifty one wards to seventy five wards and three committees for wards exceeding seventy five wards;"

(ii) after the existing clause (iv) and before the existing clause (v), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(iv-a) a women and children development, poverty alleviation, public distribution system and providing food to the needy persons committee;"
4. Amendment of section 121, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing section 121 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"121. Appeals relating to taxation.- An appeal against an assessment, or an alteration of an assessment and, in all cases in which no appeal has been made as aforesaid, an appeal against a notice of demand under section 130 may be made,-

(a) to the Commissioner, in case of Municipal Corporation; and

(b) to the concerned Regional Deputy Director of Local Bodies, in case of Municipal Council and Municipal Board."

Sagar Kumar Bhadani,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press Jaipur.